हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 01 अंक : 300 : जौनपुर, मंगलवार 01 अगस्त 2023 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य : 2 रूपया

अंजू के पाकिस्तान जाने से जुड़े मामले में 'इंटरनेशनल साजिश के पहलू की होगी जांच : गृह मंत्री

एजेन्सी

भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि राज्य पुलिस भारतीय महिला अंजू (34) के फेसबुक पर बने दोस्त से शादी रचाने के लिए पाकिस्तान जाने से जुड़े मामले में 'अंतरराष्ट्रीय साजिश के पहलू की जांच करेगी। दो बच्चों की मां अंजू ने इस्लाम स्वीकार करने के बाद इस साल 25 जुलाई को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर जिले में अपने दोस्त नसरुल्ला (29) से शादी कर ली थी। दोनों के बीच 2019 में फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी। धर्म बदलने के बाद फातिमा के नाम से पहचानी जाने वाली अंजू को इस्लाम कबूल करने पर उपहार के रूप में नकद राशि और जमीन दिए जाने की खबरें हैं। खैबर पख्तूनख्वा स्थित एक रियल एस्टेट

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मोहसिन खान अब्बासी ने अंजू और नसरुल्ला से शनिवार को उनके आवास पर मुलाकात की थी। अब्बासी ने अंजू को एक चेक सौंपा था, जिस पर दर्ज धनराशि के बारे में खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा, अंजू को 2,722 वर्ग फुट जमीन के दस्तावेज भी दिए गए थे, ताकि वह पाकिस्तान में आराम से रह सके। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के टेकनपुर कस्बे के पास स्थित बौना गांव के निवासी हैं। थॉमस ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनके परिवार के लिए अंजू अब 'मृत व्यक्ति के समान है। अंजू के मामले के बारे में पूछे जाने पर मिश्रा ने सोमवार को भोपाल में संवाददाताओं से कहा, "पाकिस्तान में जिस तरह से अंजू का स्वागत हो रहा है और उस पर उपहारों की बौछार की जा रही है, उससे कई संदेह पैदा होते हैं। इसलिए मैंने पुलिस की विशेष शाखा को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की बारीकी से जांच करे और पता लगाए कि कहीं यह कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश तो नहीं है।" मिश्रा के मुताबिक, उन्होंने अधिकारियों को 'साजिश के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह मामला प्रदेश के ग्वालियर जिले से जुड़ा हुआ है। अंजू के पिता थॉमस ने पिछले सप्ताह कहा था, "वह (अंजू) कैसे अपने दो बच्चों और पति को छोड़कर भाग गई... उसने अपने बच्चों के बारे में जरा–भी नहीं सोचा। अगर वह ऐसा करना चाहती थी, तो उसे पहले अपने पति को तलाक देना चाहिए था। अब वह हमारे लिए जीवित नहीं है।" कुछ तबकों में जारी इन अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कि इस घटना के पीछे कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि अंजू का गांव ग्वालियर में टेकनपुर कस्बे के करीब है, जहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक प्रमुख यूनिट तैनात है, थॉमस ने ऐसी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "किसी ने भी हमारे सामने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया। केवल आप (मीडिया) यह सवाल उठा रहे हैं। मेरे बच्चों में से कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। मैं इस मामले में किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं।" थॉमस ने अपनी बेटी को मानसिक रूप से परेशान और सनकी भी बताया था।

भाजपा नेता की मौत की सीबीआई जांच कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

एजेन्सी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें पटना में 13 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता की मौत की घटना की शीर्ष अदालत के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अध्यक्षता में एसआईटी जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा। पीठ ने कहा, "उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उनकी शक्तियां बहुत हैं। स्थानीय उच्च न्यायालय होने के कारण अगर उन्हें लगता है कि स्थानीय पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो वे सक्षम अधिकारियों के साथ एसआईटी का गठन कर सकते हैं तथा जांच पर निगरानी रख सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले

ली और मामले का निस्तारण कर दिया गया। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय से मामले पर तत्काल सुनवाई करने और त्वरित निर्णय लेने के लिए कहा। उसने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जहानाबाद से भाजपा नेता विजय सिंह की 'विधानसभा मार्च में भाग लेते वक्त मौत हो गई थी। पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि उनकी पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किए जाने के कारण मौत हुई जबकि पटना जिला प्रशासन ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उनके शरीर पर "चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। यह मार्च राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नीति के खिलाफ आंदोलनों के समर्थन में आयोजित किया गया था। मार्च पटना के गांधी मार्च से शुरू हुआ और उसे विधानसभा परिसर से कुछ किलोमीटर पहले रोक दिया गया था। उच्चतम न्यायालय में बिहार निवासी भूपेश नारायण द्वारा दायर याचिका में कथित तौर पर घटना के "असली दोषियों को बचाने के लिए राज्य के पुलिस प्रमुख समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि मार्च में शामिल लोगों को पुलिस ने पूर्व नियोजित तरीके से अचानक घेर लिया था।

मणिपुर हिंसा पर संसद में नहीं थमा शोर, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित

एजेन्सी

नयी दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को मणिपुर के मुद्दे पर सूचीबद्ध अल्पकालिक चर्चा शुरू नहीं हो सकी क्योंकि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सदन में बयान की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी जारी रही जिसके कारण बैठक चार बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने जब सदन की बैठक तीसरी बार अपराह्न साढ़े तीन बजे के लिए स्थगित की थी, उससे पहले उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक कर मौजूदा गतिरोध को दूर करने का रास्ता निकालने की घोषणा की थी। हालांकि अपराह्न साढ़े तीन बजे जब बैठक शुरू हुई तब भी सदन में विपक्ष की नारेबाजी जारी रही जिससे संकेत मिलता है कि इस बैठक में गतिरोध दूर करने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। साढ़े तीन बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा कि पूरा देश यह सब देख रहा है। उन्होंने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि उच्च सदन को आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए।

हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मणिपुर का मुद्दा गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाती है और सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है तो फिर चर्चा तत्काल शुरू की जानी चाहिए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। सभापति ने भी सदस्यों से चर्चा शुरू करने के लिए कहा। लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने महज तीन मिनट बाद ही, तीन बजकर 33 मिनट पर बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर, गोवा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित सदस्य सदानंद शेत तलावड़े ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। सभापति धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 65 नोटिस मिले हैं। सभापति ने कहा कि उन्होंने नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम और उनके मुद्दों का उल्लेख करने की परिपाटी आरंभ की है। उन्होंने सदस्यों से पूछा कि क्या उन्हें नोटिस देने वाले सभी सदस्यों के नाम पढ़ने चाहिए। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई।

3 सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार जब मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है तो ऐसे में विपक्षी सदस्य सदन का महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर चर्चा से "भागने का आरोप लगाया। गोयल ने कहा, "हम आज ही इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। आप दोपहर दो बजे चर्चा शुरु करें। धनखड़ ने कहा कि वह 20 जुलाई को नियम 176 के तहत मिले नोटिस को स्वीकार कर चुके हैं और सरकार ने चर्चा की हामी भर दी है।

बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्जी की हालत अभी भी गंभीर

एजेन्सी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्जी का सोमवार को सीटी स्कैन कराया गया। कोलकाता के निजी अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूत्रों ने बताया कि सीटी स्कैन की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही मेडिकल बोर्ड आगे कोई फैसला करेगा।

सीटी स्कैन रिपोर्ट से मेडिकल बोर्ड यह पता लगा सकेगा कि उनके फेफड़ों में कितना संक्रमण है। हालांकि, सोमवार सुबह तक उनकी चिकित्सीय स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। निमोनिया से प्रभावित होने के कारण उन्हें इनवेसिव वेंटिलेटर पर रखा गया है। बाइलैटरल निमोनिया को नियंत्रण में रखने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स की खुराक दी जा रही है। हालांकि, उनका बल्ड प्रेशर स्तर कमोबेश स्थिर है। कई बार तो वह कॉल का जवाब भी दे रहे हैं और अपनी आंखें भी झपका रहे हैं। वह लिक्विड डायट पर हैं।

किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं : योगी

एजेन्सी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम ने कमजोर लोगों को सताने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए सोमवार को कहा कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। सीएम ने अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर दौरे पर पहुंचे है। सीएम ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन कर मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम ने जनता दर्शन किया और आने वाले सभी फरियादियों से बातचीत की और उनकी फरियाद सुनी। जिसके बाद सीएम ने सभी की समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने के लिए संकल्पित है। जनता दर्शन के संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने करीब 400 लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इलाज के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने का अनुरोध करने वाले लोगों को सरकार की ओर से सहायता किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व एवं पुलिस से जुड़े मामलों को पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश दिया। सीएम ने सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

पंचायत में पहुंचे बीजेपी नेता पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला

एजेन्सी

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पंचायत में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय पदाधिकारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि हमले के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी के मुताबिक, बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में भाजपा के मनियर मंडल के महामंत्री अजित सिंह रविवार दोपहर भूमि विवाद से जुड़ी एक पंचायत में पहुंचे थे, तभी उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। अधिकारी ने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक,504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) व 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

ज्ञानवापी पर योगी का बड़ा बयान, बोले, मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा

एजेन्सी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने कहा गलती मुस्लिम पक्ष की ओर हुई तो उनकी तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानवापी में त्रिशूल क्या कर रहा है? ज्ञानवापी में सनातन साक्ष्य मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ज्ञानवापी विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम समाधान चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं। यह प्रतिमा हिंदुओं ने नहीं रखी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है। मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए।

सरकार आज ही मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष बोला विस्तार से हो बात

एजेन्सी

नयी दिल्ली। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत विस्तार से चर्चा कराए जाने की मांग रखी है। चर्चा के लिए राज्यसभा के सभापति को 65 सांसदों ने नोटिस दिए हैं। वहीं राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि चर्चा आज यानी सोमवार को ही हो सकती है। गोयल ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर यह चर्चा दोपहर 2 बजे से शुरू कराई जा सकती है सरकार इसके लिए तैयार है, लेकिन यह चर्चा नियम 176 के तहत करवाई जाए। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे और हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए नेता प्रतिपक्ष मलिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम नियम 267 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विनती है, इंडिया गठबंधन के कई सांसद मणिपुर के हालात देखकर लौटे हैं मणिपुर जल रहा है। इससे पहले सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के लिए 65 नोटिस प्राप्त हुए हैं। नियम 267 के अंतर्गत सदन की शेष सभी कार्रवाई को निलंबित करते हुए विस्तृत चर्चा कराई जाती है। सोमवार को राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है, बावजूद इसके विपक्ष द्वारा राज्यसभा की कार्यवाही के 9 दिन व्यर्थ किए गए। गोयल ने कहा हम आज के आज ही नियम 176 के अंतर्गत मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं।

दिल्ली में डेंगू का कहर शुरू

एजेन्सी/नयी दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने से जलमग्न हुए इलाकों के बीच अब डेंगू का कहर शुरू हो गया है। पिछले सप्ताह डेंगू के 56 ताजा मामले सामने आए, जिससे मामलों की संख्या 240 से अधिक हो गई। सोमवार को नगर निगम की एक रिपोर्ट ने यह जानकारी साझा की। राष्ट्रीय राजधानी में 22 जुलाई तक वेक्टर जनित बीमारी के 187 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 28 जुलाई तक यह संख्या 243 थी।

झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार, 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित

एजेन्सी

रांची। 2 दिन के अवकाश के बाद आज झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत होने से पहले ही प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।

जानकारी के मुताबिक सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने इंडिया के बैनर तले मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और भाजपा विधायक समरी लाल के बीच पार्टी के चरित्र को लेकर बहस भी हुई। समरी लाल ने इंडिया को इंदिरा की पार्टी कहा तो वहीं इरफान ने भाजपा का आदिवासी विरोधी बताया। हालांकि हंगामे के बीच निर्धारित समय से सदन शुरू हुआ। सदन शुरू होते ही भाजपा की ओर से हंगामा शुरू हुआ। माले विधायक विनोद सिंह ने महिला सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने थानों में महिला दारोगा की नियुक्ति को लेकर भी सवाल पूछा। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि इस दिशा में काम हो रहा है। प्रश्नकाल में विधायक प्रदीप यादव ने मणिपुर की घटना का जिक्र किया और केंद्र सरकार को संज्ञान लेने को कहा। वहीं, इसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि झारखंड विधानसभा मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हुआ था। 4 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। बताया जा रहा है कि इस मानसून सत्र में बीजेपी हेमंत सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी। इसके लिए बीजेपी ने रणनीती भी बना ली है।

मेरे परिवार का कोई सदस्य डब्ल्यूएफआई चुनाव में दावेदारी पेश नहीं कर रहा : बृज भूषण

एजेन्सी/नयी दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने सोमवार को कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य राष्ट्रीय खेल संस्था के आगामी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेगा लेकिन उन्होंने दोहराया कि उनके गुट को 22 राज्य संघों का समर्थन हासिल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृज भूषण ने दावा किया है कि रविवार को उनकी मेजबानी में हुई बैठक में 25 राज्य इकाइयों में से 22 ने हिस्सा लिया। उन्होंने साथ ही कहा कि महासंघ के 12 अगस्त को होने वाले चुनावों के विभिन्न पदों के लिए 'उनके उम्मीदवारों की घोषणा सोमवार को की जाएगी। बृज भूषण सोमवार को डब्ल्यूएफआई चुनावों के लिए नामांकन के अंतिम दिन यहां भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के कार्यालय भी गए। बृज भूषण ने कहा, "आज नामांकन का अंतिम दिन है, 22 राज्य संघों के सदस्य यहां थे और वे मिलने के लिए आए हैं और अब अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। इनमें मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा, "पहले चुनाव होने दीजिए और फिर जो भी जीतेगा वह अपना काम करेगा। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक तथा एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट सहित देश के शीर्ष छह पहलवानों ने बृज भूषण पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे ।

अयोध्या के साथ-साथ रांची में भी तैयार हो रहा है राम मंदिर, जल्द ही होगा शिलान्यास

एजेन्सी

रांची। कुछ महीनों बाद एक नहीं बल्कि 2 राम मंदिर बनकर तैयार होने वाले हैं। जी हां, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के साथ– साथ झारखंड के रांची के कुच्चू गांव में भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कुच्चू गांव में राम मंदिर का निर्माण यहां के ही ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर करवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही निर्माण कार्य हो जाएगा। वहीं, राम मंदिर समिति के अध्यक्ष और बीजेपी से राज्य सभा सांसद आदित्य साहू ने बताया कि यह राम मंदिर अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसका लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। 30 प्रतिशत आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। जनवरी में अयोध्या का राम मंदिर का शिलान्यास की बातें सामने आ रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि उसी समय हम भी इस मंदिर का शिलान्यास करें। उन्होंने बताया मंदिर तैयार हो जाने से पहले यहां राम भगवान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस दौरान बनारस से करीब 15 से 20 पंडित बुलाने पर चर्चा हो रही है। आदित्य साहू ने बताया कि यहां लोगों के रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। यहां एक छोटा गेस्ट हाउस है, उसकी हम मरम्मत करा रहे हैं। इसमें दूर–दूर से आए लोग आराम से रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के पास में एक खूबसूरत मंडप भी बनाया जा रहा है। यह मंडप शादी–ब्याह के लिए बनाया जा रहा है। आदित्य साहू ने बताया इस मंडप में हिंदू धर्म के लोग शादी कर पाएंगे।

सम्पादकीय

अघोषित ड्रोन युद्ध

भारत में युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिये पाकिस्तान बड़े पैमाने पर ड्रोन के जरिये नशीले पदार्थों की आपूर्ति करता रहा है। यह खेल देश के सीमावर्ती इलाकों में लंबे समय से जारी है। पाक की धरती से उड़ने वाले ये ड्रोन कश्मीर व पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में आतंकियों को हथियार व पैसा मुहैया कराने के लिये नशे की खेप लगातार गिराते रहे हैं। जबकि पाक ने कभी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया कि उसकी धरती से लगातार भारत विरोधी गतिविधियां ड्रोन के जरिये जारी हैं। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष रक्षा सहायक मलिक मोहम्मद खान ने एक टीवी साक्षात्कार के दौरान स्वीकार किया कि सीमा पार से भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिये पाकिस्तानी ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल, मोहम्मद खान प्रांतीय विधानसभा में कसूर शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने अपने इलाके में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिये विशेष पैकेज की मांग की थी। इसी मांग के लिये दबाव बनाने के लिये उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर समय रहते बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिलती तो उस इलाके के युवा भी उन तस्करों में शामिल हो सकते हैं, जो नियंत्रण रेखा के करीब स्थित कसूर के रास्ते भारत में हेरोइन भेजने के लिये ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जाहिर है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार की यह स्वीकारोक्ति इस बात की पुष्टि करती है कि शरीफ सरकार की नाक के नीचे ड्रोन के जरिये मादक पदार्थों का धंधा धड़ल्ले से जारी है। यानी नशा तस्करों को रोकने के लिये कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। दरअसल, अब तक पर्याप्त सबूतों के बावजूद पाकिस्तान लंबे समय से किसी भी रूप में सीमा पार से आतंकवाद को सहायता या बढ़ावा देने में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार करता रहा है। पिछले दिनों जम्मू–कश्मीर व सीमावर्ती राज्य पंजाब में ड्रोन के जरिये ड्रग्स व हथियार की खेप गिराने की तमाम घटनाएं सामने आई हैं। कई ड्रोनों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार भी गिराया है। हाल ही में मादक द्रव्यों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृहमंत्री अमित शाह से ड्रोन पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया था। साथ ही उन्हें बताया था कि सीमा पार से हथियारों और हेरोइन की तस्करी के लिये बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जवाब में शाह ने घोषणा की थी कि कई तरह के प्रतिबंधों वाली नई ड्रोन नीति की घोषणा जल्दी की जाएगी। निस्संदेह, ड्रोन तस्करी के खतरे को देखते हुए इसके मुकाबले को एक मजबूत नीति की जरूरत है। वहीं पाक अधिकारी की स्वीकारोक्ति के बाद इस मुद्दे पर पाक को घेरने की कोई कसर भारत को नहीं छोड़नी चाहिए। यह अच्छा मौका है कि नार्को आतंकवाद को संरक्षण देने की पाक नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब किया जाए।

मरहम की बजाये सियासत

मोदी सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण सिकुड़ता भारतीय मध्यम वर्ग इस मायने में देश की राजनीति का यह स्वरूप वाकई दुखद और निराशाजनक है जिसमें केन्द्र का सत्तारुढ़ दल और सरकार की किसी त्रासदी में पीड़ित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाये सियासत करने में अधिक रुचि है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान आई हर तरह

की आपदाओं, त्रासदियों व संकटों के बहाने सामाजिक ध्रुवीकरण करने और वोट बैंक साधने के जो प्रयोग हो रहे हैं वे इसलिये निन्दनीय हैं क्योंकि इसके कारण तकलीफ में पड़े लोगों के दुख–दर्द तो दूर होने से रहे, उलटे सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया तेज हो रही है और परस्पर वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। साम्प्रदायिक टकराव में जल रहे उत्तर–पूर्वी राज्य मणिपुर के मामले में यही हो रहा है। अनेक गलतियां करने के बाद भी केन्द्र के साथ वहां राज्य में भी सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी इसे अब भी एक राजनैतिक मुद्दा ही बनाये हुए है।

म्यांमार जैसे देश से लगी सीमा पर स्थित होने के कारण मणिपुर के घटनाक्रम की संवेदनशीलता को केन्द्र व राज्य की सरकारें तथा भाजपा दोनों ही जैसे समझना भी नहीं चाहतीं– ऐसे वक्त में भी जब इसकी आग अन्य पड़ोसी राज्यों में लगातार फैल रही है। अब तो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने इस हिंसा के पीछे चीन का हाथ होने का संदेह व्यक्त किया है तथा पीड़ित कुकी समुदाय अपना अलग प्रशासन मांगने लग गये हैं। तब भी। तीन महीनों से यहां जारी हिंसा को ढंककर रखने वाली केन्द्र सरकार की नींद मानों तब जाकर खुली जब दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने से व्यथित सुप्रीम कोर्ट ने स्वतरू संज्ञान लिया और चेतावनी दी कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो वह खुद कार्रवाई करेगी।

रूस–यूक्रेन का युद्ध और फ्रांस की हिंसा को भी रोक सकने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसके बाद ही हरकत में आये पर संसद के भीतर नहीं वरन बाहर आकर मणिपुर पर बोलेय वह भी कुल जमा 36 सेकंड ही, जबकि संसद उनके बयान के इंतजार में ठप पड़ी है और उनके खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टेबल पर अटका हुआ है। संसद में इस भीषण घटना पर बयान देने से बचने–बचाने का नाटक पिछले डेढ़ हफ्ते से जारी है। प्रधानमंत्री लोकसभा में आकर इस पर बयान दें, इस मांग को लेकर सम्पूर्ण विपक्ष अड़ा हुआ है और सत्तारुढ़ दल अपने पीएम को छिपाती फिर रही है। ऐसे समय में जब सत्ता पक्ष को मणिपुर में लोगों के साथ खड़े होना था, उसकी जगह पर हाल ही में बने संयुक्त विपक्षी गठबंधन इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूजिव एलाएंस) के 21 सदस्यों ने शनिवार–रविवार को यहां आकर लोगों से बात की। यह दल जमीनी हकीकत से सरकार व संसद को एक रिपोर्ट के जरिये अवगत करायेगा एवं शांति बहाली के उपाय सुझाएगा। बहरहाल, जिन मोदी जी ने मणिपुर की घटना पर संसद के बाहर अपनी तीव्र पीड़ा व क्रोध को दर्शाया है, वह इसलिये वास्तविक नहीं लगता क्योंकि अगर वे सचमुच पीड़ा से भर गये होते तो मणिपुर के प्रभावितों को गले लगाते और वाकई क्रोधित रहते तो दोषियों को दण्डित करते। दुनिया भर में इसे लेकर भारत की पिट रही भद से निर्लिप्त मोदी राजस्थान के सीकर में भव्य मंच सजाकर व भीड़ जुटाकर विपक्षी गठबन्धन को आतंकवादी संगठनों से जोड़ रहे हैं तो उनके खासमखास व घटना के लिये उतने ही उत्तरदायी गृहमंत्री मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियां कर रहे हैं।

हिन्द प्रशांत क्षेत्र और फ्रांस

आदित्य नारायण

श्रीलंका के आर्थिक संकट से कुछ सम्भलने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनूएल मैक्रों श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे हैं। श्रीलंका और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रीलंका पहुंचने वाले वह पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। मैक्रों और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंगे में बातचीत के बाद फ्रांस ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में सहायता का वायदा किया। दोनों देशों में सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा हुई और दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं की वार्ता के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इमेनूएल मैक्रों ने हिन्द प्रशांत क्षेत्र पर भारतीय रुख का जबरदस्त ढंग से समर्थन किया और रानिल विक्रमसिंगे से कहा कि हिन्द महासागर के दो देश श्रीलंका और फ्रांस खुला समावेशी और समृद्ध हिन्द प्रशांत क्षेत्र का लक्ष्य साझा करते हैं और दोनों देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। भारत और फ्रांस भी हिन्द प्रशांत क्षेत्र के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और इसके संप्रभुता–क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक संतुलित और स्थिर व्यवस्था बनने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और इस क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता, विकास को विश्व शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक माना था। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने पिछले वर्ष हिंद महासागर के यूनियन द्वीप में संयुक्त पैट्रोलिंग की थी। यह द्वीप हिंद महासागर में फ्रांस के नियंत्रण वाला विदेशी क्षेत्र है। यह मेडागास्कर और मॉरीशस से निकट भी है। पी 81 एयरक्राफ्ट के जरिए ही यह पैट्रोलिंग की गई थी। फ्रांस हिंद महासागर में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति है जिसके अड्डे अबू धाबी, जिबूती, मायोट, रियूनियन द्वीप में हैं और इसके साथ ही दक्षिणी प्रशान्त महासागर में फ्रेंच पोलिनेशिया और न्यू कैलेडोनिया में भी इसके नौ सैनिक अड्डे हैं।

इसी साल फ्रांस इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन का 23वां पूर्ण सदस्य देश बना है जिससे हिंद महासागर को चीन जैसे देशों के एकाधिकारवादी मानसिकता के दायरे से बाहर निकालने की फ्रांस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विस्तारवादी नीति के तहत चीन हिंद–प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आर्थिक व भौगोलिक विस्तार कर विश्व में वर्चस्व कायम करना चाहता है। चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये से गंभीर संकट पैदा हो रहा है और यह भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया है। इस पृष्ठभूमि में क्वॉड की सर्व समावेशी भूमिका को विश्व के हित में प्रभावशाली रूप में देखा जा रहा है।

हिंद–प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाने के लिए और विश्व की चुनौतियों पर एक साथ काम करने के लिए 24 मई, 2022 को टोक्यो में आयोजित क्वॉड देशों के तीसरे शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा तथा संप्रभुता की रक्षा के साथ वैश्विक भू–राजनीतिक व भू–आर्थिक परिस्थितियों के कारण लोकतांत्रिक व तानाशाही देशों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए 13 देशों का एक आर्थिक मंच बनाया गया था जिसमें भारत, आस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ ब्रूनेई, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया व वियतनाम शामिल हैं। इससे हिंद–प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग के साथ एक बड़े आर्थिक सहयोग संगठन की शुरुआत टोक्यो में हो चुकी है जिससे कोरोना संकट काल के बाद व रूस–यूक्रेन युद्ध से उपजी समस्याओं जैसे आपूर्ति शृंखला, महंगाई, डिजिटल धोखाधड़ी, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने की बात की गई है जो विश्व की निर्भरता को चीन से कम भी करेगा। 13 देशों के बने संगठन आईपीईएफ (इंडो– पैसिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क) में वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीडीपी का 40 प्रतिशत हिस्सा है जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण नए आर्थिक मंच के रूप में उभरने की संभावनाओं से भरा है। श्रीलंका भी चीन के ऋण जाल में फंसकर अपना बुरा हाल करवा चुका है। उसने श्रीलंका के हेबन टोटा बंदरगाह पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर कब्जे के कारण ब्लूचों के कड़े विरोध और हमलों के चलते उसके वापिस लौटने की नौबत आ चुकी है। मालदीव और म्यांमार में भी उसकी साजिशें सफल नहीं हो रही हैं। दक्षिणी चीन सागर में उसने भय और अस्थिरता का माहौल कायम किया हुआ है। भारत ने हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर में नौगमन की स्वतंत्रता, महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्गों से अबाधित आवाजाही को एक नया वैश्विक आंदोलन बना ध्दया है और भारत को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। बेहतर यही होगा कि श्रीलंका चीन के जाल से बाहर निकल इस आंदोलन का भागीदार बने और खुद को मजबूत बनाए। भारत, फ्रांस और अन्य देश श्रीलंका की हरसम्भव मदद करने के लिए तैयार हैं।

मुख्य न्यायाधीश की गरिमा

भारत में इंटरनेट क्रान्ति होने के बाद जिस प्रकार 'ट्रोल आर्मी' का उदय हुआ है उससे सार्वजनिक जीवन में कार्यरत प्रमुख व्यक्तियों के बारे में रचनात्मक आलोचना की जगह सड़क–छाप व भद्दी–भद्दी गालियां आदि देने की नकारात्मक व अश्लील प्रवृत्ति ने भी जन्म लिया है। लोकतन्त्र में तीखी आलोचना की इजाजत है मगर शालीनता के दायरे में। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि शालीनता या नैतिकता अथवा अश्लीलता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सापेक्ष अवधारणा (रिलेटिव कांसेप्ट) होती है। उनका यह तर्क अनुचित है क्योंकि 'गाली' को सापेक्षता के दायरे में रख कर नहीं देखा जा सकता वह समाज के हर वर्ग में 'गाली' ही होती है और अश्लीलता के घेरे में ही आती है। मगर इससे भी बड़ा सवाल तब पैदा होता है जब कुछ लोग भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका या इसके न्यायमूर्तियों की उनके द्वारा दिये गये फैसलों से नाराज होकर निन्दा करते हैं और 'संविधान सम्मत नागरिक आचरण' की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। पिछले कुछ समय से भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री डी. वाई. चन्द्रचूड़ के खिलाफ कुछ लोग न केवल बेहूदा व अश्लील ट्रोल कर रहे हैं बल्कि उनकी व्यक्तिगत आलोचना करने में सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं। इन लोगों की समझ में प्रधान न्यायाधीश भी कोई साधारण राजनीतिज्ञ हैं जिनकी आलोचना सार्वजनिक रूप से की जा सकती है और उन्हें गालियां तक दी जा सकती हैं। सबसे पहले यह समझा जाना चाहिए कि प्रधान न्यायाधीश ही देश के संविधान के रक्षक राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और यदि देश में कभी ऐसा अवसर आ जाये जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति में से कोई भी अपने पद पर न हो तो वह ही राष्ट्रपति के पद को अस्थायी रूप से संभालते हैं। ऐसा भारत में एक बार हो चुका है जब 1969 में डा. जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और उसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी एक प्रत्याशी बन गये थे। तब सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश स्व. हिदायतुल्लाह ने अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद संभाला था। अतः श्री चन्द्रचूड़ को गाली देना सीधे संविधान को गाली देने की समान ही माना जायेगा और ऐसा करने वालों के लिए भारतीय दंड संहिता में उचित सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही ट्रोल आर्मी के सदस्यों को यह भी सोचना चाहिए कि भारत की न्यायपालिका 'सरकार' का अंग नहीं होती और इसकी प्रमुख जिम्मेदारी पूरे देश में संविधान का शासन देखने की होती है। इसके पास सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों को ही संविधान की कसौटी पर कस कर 'अवैध' करार देने का अधिकार होता है। न्यायपालिका की अपनी कोई राजनैतिक विचारधारा नहीं होती और इसका काम यही होता है कि किसी भी राजनैतिक विचारधारा की लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हर हालत में संविधान के अनुसार काम करे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में 'संविधान का शासन' होता है चाहे सरकार कांग्रेस की हो अथवा भाजपा की लेकिन यह हमारी न्यायपालिका और प्रधान न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड़ का बड़प्पन और महानता है कि वह अपने बारे में किये गये ट्रोलों का कभी संज्ञान नहीं लेते और अपना कार्य 'विक्रमादित्य' की भांति करते रहते हैं परन्तु भारत के लोकतन्त्र प्रेमी इस स्थिति को सही नहीं मानते और उनका कहना रहा है कि इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 19 (ए) के तमाम उपबन्धों को लागू करके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू की दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने 1950 में ही संविधान में पहला संशोधन करके यह सुनिश्चित किया था कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का उपयोग हिंसा भड़काने या समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए नहीं किया जा सकता और आलोचना शालीनता के दायरे में रह कर ही की जा सकती है। इस संशोधन को तभी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। उस समय के हिन्दू महासभा के नेता एन.सी. चटर्जी इस संशोधन के सख्त खिलाफ थे।इतिहास के इन दस्तावेजों की रोशनी में हमें ट्रोल आर्मी के असभ्य व निन्दनीय व्यवहार की समालोचना करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हम अपने लोकतन्त्र को 'गाली तन्त्र' में बदल देना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या इसके प्रधान न्यायाधीश के हाथ अपने संवैधानिक दायित्वों से बंधे होते हैं और वे जो भी फैसला देते हैं वह केवल संविधान की 'रुह' से ही निकलता है। अतः मणिपुर राज्य की स्थिति के बारे में उनके द्वारा दिये गये निर्णय या टिप्पणियों को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। मगर तमिलनाडु के एक राजनैतिक टिप्पणीकार कहे जाने वाले व्यक्ति 'बदरी शेषाद्रि' ने इस बारे में एक वीडियो बनाई और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। इसमें कहा गया है कि ''सर्वोच्च न्यायालय स्वयं को कितना बड़ा समझ रहा है, मुझे इसके बारे में शब्द नहीं मिल रहा है। प्रधान न्यायाधीश को एक रिवाल्वर दे दिया जाना चाहिए और उनसे कहा जाना चाहिए कि वह मणिपुर में जाकर शान्ति–व्यवस्था कर दें। क्या आप सरकार के कार्यक्षेत्र में नाम का भी दखल दे सकते हैं? आप वहां की राज्य सरकार के खिलाफ क्या खता देख रहे हैं? वहां दो समूह आपस में लड़ रहे हैं–––यह पहाड़ी इलाका है––––साथ ही बहुत उलझावों से भरी धरती है''। इस वीडियो के खिलाफ तमिलनाडु के पेराम्बदूर के एक वकील ने एफआईआर दर्ज कराई जिसका संज्ञान लेते हुए इलाके की पुलिस ने दंड संहिता की विभिन्न सम्बन्धित धाराओं में शेषाद्रि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जहां से उसे 11 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिये गये। गौर से देखा जाये तो तमिलनाडु पुलिस ने संविधान के अनुसार कदम उठा कर शेषाद्रि जैसे लोगों को समझाने की कोशिश की है कि संविधान का शासन पूरे देश में देखने की जिम्मेदारी से बंधे भारत के न्यायाधीश को ओछी व संकीर्ण राजनीति में नहीं घसीटा जा सकता। वह कोई राजनैतिक व्यक्ति भी नहीं हैं कि अपना दर्द बयां कर सकें और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान न्यायाधीश के अपने संवैधानिक दायित्व निभाने के काम में कोई भी व्यक्ति अड़ंगा नहीं लगा सकता है। भारत की न्यायपालिका तो वह है जिसने 12 जून, 1975 को इलाहाबाद में तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. इन्दिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को ही कानूनी नुक्तों के तहत अवैध करार दे दिया था।

विपक्ष को यह आभास होना चाहिए कि जनता सब देख और समझ रही

संजय गुप्त

देश को शर्मसार करने वाली मणिपुर की घटना का वीडियो आने के बाद कांग्रेस सहित नए बने विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस के घटकों ने जिस तरह संसद न चलने देने की ठानी, उसे सही ठहराना मुश्किल है, क्योंकि समय की मांग यही थी कि इस घटना पर संसद में तत्काल गहन चर्चा होती। हालांकि उक्त वीडियो सामने आते ही प्रधानमंत्री ने मीडिया के सामने आकर घटना की भर्त्सना करते हुए यह कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह इस पर अड़ गया कि संसद में मणिपुर पर चर्चा तब होने दी जाएगी, जब पहले प्रधानमंत्री अपना बयान देंगे। इसे लेकर भी पक्ष–विपक्ष में टकराव हो गया कि मणिपुर पर बहस किस नियम के तहत हो। इस टकराव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने अपने हंगामे से उसे नाकाम कर दिया और तर्क यह दिया कि उनकी कथनी–करनी में अंतर है। साफ है कि विपक्ष को संसद ठप करने का बहाना चाहिए था। वह गृह मंत्री को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया, जिसे मंजूरी भी मिल गई और यह भी तय हो गया कि जल्द ही उस पर बहस होगी। इसके बाद संसद चलने दी जानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष हंगामा करने को ही प्राथमिकता देता रहा। मजबूरी में सरकार को हंगामे के बीच विधेयक पेश और पारित कराने पड़ रहे हैं। यह विचित्र है कि विपक्ष इसे लेकर शिकायत भी कर रहा है और चर्चा में भी भाग नहीं ले रहा है। पिछले कुछ समय से यह देखने को मिल रहा है कि संसद का प्रत्येक सत्र शुरू होते ही विपक्ष किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा शुरू कर देता है और सदन नहीं चलने देता। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि संसद सत्र शुरू होने के ठीक पहले ऐसा कोई मामला आ जाता है, जिससे विपक्ष को हंगामा करने में आसानी होती है। कभी पेगाससस जासूसी मामला सामने आया तो कभी अदाणी समूह को लेकर अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रपट। किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष जिस तरह हंगामा करने को तरजीह देने लगा है, उससे तो यही लगता है किसंसद चलाने में उसकी दिलचस्पी ही नहीं रही। लगता है वह इससे अनजान है कि जरूरी विधेयक समय रहते पारित न होने से देश के काम रुकते हैं। विपक्ष को यह आभास होना चाहिए कि जनता यह अच्छे से देख और समझ रही है कि वह किसी न किसी बहाने संसद को नहीं चलने देना चाहता। इसके कहीं कोई प्रमाण नहीं कि किसी दल ने संसद में हंगामा करके राजनीतिक लाभ हासिल किया हो या फिर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में सफल रहा हो। यह ठीक है कि लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन यदि विपक्ष यह आशा कर रहा है कि संसद को बाधित कर वह अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहा है तो यह उसकी भूल ही है। उसे यह पता होना चाहिए कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 2014 के मुकाबले कहीं अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी। विपक्ष को पता है कि इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव में उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों वह उसे अपनी जीत समझ रहा है? निःसंदेह उसने अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को घेरने के लिए अपनी तैयारी कर ली होगी, लेकिन सत्तापक्ष भी तो तैयारी कर रहा होगा। यह तय है कि सरकार भी विपक्ष को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। वह मणिपुर पर बयान देने के साथ विपक्ष शासित राज्यों और खासकर बंगाल की घटनाओं का भी उल्लेख कर सकती है। जहां तक मणिपुर में दो महीने से जारी हिंसक टकराव की बात है, वह वास्तव में गंभीर है, लेकिन वहां के इतिहास को देखें तो विभिन्न गुटों के बीच पहले भी हिंसक टकराव होते रहे हैं। एक समूह के लोग दूसरे के बैरी बन जाते रहे हैं। इस बैर भाव के कारणों की तह तक जाना और उस पर सार्थक चर्चा जरूरी है। यह तभी संभव है, जब सदन में खुलकर चर्चा हो। कांग्रेस को यह याद रखना चाहिए कि मणिपुर में उसके शासन के समय जब–जब हिंसा हुई तब–तब क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संसद में चर्चा की शुरुआत की। 1993 में मणिपुर में नगा–कुकी के बीच संघर्ष में करीब सात सौ लोग मारे गए थे। तबके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां गए अवश्य थे, लेकिन चंद घंटों के लिए, जबकि इस बार गृह मंत्री अमित शाह वहां चार दिन रहे। इस दौरान उन्होंने वहां सभी समुदायों से संवाद किया। उन्होंने गृह राज्य मंत्री को भी वहां 22 दिनों के लिए भेजा। केंद्र से अधिकारी भी वहां भेजे। स्पष्ट है कि गृह मंत्री ने मणिपुर की हिंसा थामने के लिए भरसक प्रयास किए। कांग्रेस का यह आरोप निराधार ही है कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वह नियमित तौर पर वहां के हालात की समीक्षा करते रहे। यह आरोप सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कि प्रधानमंत्री मणिपुर की स्थिति नियंत्रित नहीं करना चाहते थे। वह तो पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्यधारा में लाने के प्रयास 2014 से ही कर रहे हैं। इससे वहां बदलाव भी आया है और वह दिख भी रहा है। चूंकि संसद में इस या उस बहाने हंगामा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसलिए समय आ गया है कि ऐसी कोई व्यवस्था बने, जिससे संसद राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदार सही से कर सके। कोई भी समस्या हो, उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, न कि हंगामा। विडंबना यह है कि अब हंगामा अधिक होता है और काम कम। कई बार तो पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। इससे संसद की गरिमा गिरती है और लोकतंत्र की बदनामी होती है। अब यह आवश्यक हो गया है कि जो भी सांसद संसद न चलने दे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे नियम–कायदे बनने चाहिए जिससे सदन की कार्यवाही बाधित न होने पाए, क्योंकि लगातार ऐसा होने से लोकतंत्र का उपहास ही नहीं उड़ता, देश का विकास भी थमता है। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि संसद सत्र शुरू होने के ठीक पहले ऐसा कोई मामला आ जाता है, जिससे विपक्ष को हंगामा करने में आसानी होती है। कभी पेगाससस जासूसी मामला सामने आया तो कभी अदाणी समूह को लेकर अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रपट। किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष जिस तरह हंगामा करने को तरजीह देने लगा है।

आज का राशिफल

मेष :– योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। विरोधियों की प्रबलता से कार्य क्षेत्र में कठिनाईयाँ संभव। जीविका क्षेत्र में नए आयाम उत्साहित करेंगे।

बृषभ :– रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर उत्साह का संचार करेंगे, परन्तु आवेश में लिया गया निर्णय हानिकारक हो सकता है। जो बीत गयी उसे भूल वर्तमान में जीने की चेष्ठा करें।

मिथुन :– दूसरों की सफलता से अपने अन्दर हीन भावना ना पाले। नौकरी का वातावरण थोड़ा अरुचिकर और स्थान परिवर्तन के भी योग हैं। किसी सहकर्मी खराब व्यवहार से कष्ट संभव।

कर्क :– प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने से मन प्रसन्न होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का भरपूर लाभ उठाने का समय आ गया है। किसी विपरीत लिंगी सम्बन्ध में आकर्षण बढ़ेगा।

सिंह :– नाजुक सम्बन्धों मे भावनात्मक ताल–मेल बिठाने का प्रयत्न करें। नये कायां के क्रियान्वयन के लिए प्रयत्न तीव। भावनात्मक अभिव्यक्ति सम्बन्धों मधुरता बढेगी। कुछ नये उत्साह की अनुभूति करेंगे।

कन्या :– पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। दूसरों की आलोचना का अपने मनोबल पर असर न पड़ने दें। ग्रहों की अनुकूलता से प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे।

तुला :– कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुरूप चलने का प्रयत्न करें। शिक्षा–प्रतियोगिता के दिशा में परिश्रम तीव्र होगा। कुछ आर्थिक प्रगति के लिए मन में नई–नई युक्तियाँ उत्पन्न होंगी।

वृश्चिक :– आसीम प्रतिभाओं के बावजूद भी हीन मन प्रतिभाओं के लाभ से वन्चित होगा, अतरू इसे सुधारें। रोजगार की समस्याओं को लेकर मन चिन्तित होंगा। मन आपसी तालमेल बैठाने में असमर्थ होगा।

धनु :– दूसरों की बात इधर से उधर करना आपको शोभा नही देता। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होग। परिवारिक संबंधों में कटुता पैदा न होने दें। किसी बड़ी यात्रा के प्रति मन उत्साहित होगा।

मकर :– अपनी क्षमताओं व गुणवत्ता पर भरोसा रखें आगे बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। पुराने संबंधी से आकस्मिक भेंट संभव। रोजगार में सफलता के योग हैं। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में व्यय संभव।

कुंभ :– कल्पनाएं व आकांक्षाएं अपनी सार्थकता हेतु आपको उद्वेलित करेंगी। राजनैतिक सरगर्मियाँ आपकी व्यस्तता बढ़ाएंगी। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानी पैदा हो सकती हैं।

मीन :– कोई महत्वपूर्ण आकांक्षा अपनी सार्थकता हेतु आपको उद्वेलित करेंगी। अपकी सारी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। थोड़ धैर्य पूर्वक वक्त का इन्तजार करें। स्वास्य के प्रति सचेत रहें।

रियल टाइम खतौनी, किसान बीमा दुर्घटना संबंधी बैठक सम्पन्न

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में रियल टाइम खतौनी, किसान बीमा दुर्घटना संबंधी बैठक सोमवार सायं कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा स्वामित्व योजना, एग्रीकल्चर सेंसस, डिजिटल क्रॉप सर्वे, घरौनी वितरण, जल जीवन मिशन आदि के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने तहसीलवार उपजिलाधिकारी व तहसीलदार से स्वामित्व योजना के प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति को तेज करें और अनमैप होल्डिंग को शून्य कराएं।

बैठक में समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आबादी सर्वेक्षण में ऐसे गांव जिनका विवरण सर्वे विभाग को प्रेषित नहीं किया गया है उनका प्रेषण कराये और जितने गांव के विवरण प्रेषित किए गए हैं सर्वप्रथम उन्हें लॉक किया जाए।

घरौंनी के वितरण में संतोषजनक वृद्धि न होने एवं इस माह में कोई घरौनी वितरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष इसमे वृद्धि करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया।

आधे अधूरे स्वामित्व की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बड़े गांव का चुनाव करें एवं जहां अधिक मजरा है उसका स्वामित्व कराना सुनिश्चित करें।

इसके पश्चात जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत जनपद में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान एक्सईएन जल निगम को कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य की प्रगति ठीक कराने का निर्देश दिया। निर्माणाधीन कार्य स्थलों पर एईध्जेई की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि जब तक विवादों का समाधान नहीं हो जाता तब तक इफकॉन वेलस्पन तथा जल निगम के एईध्जेई मौके पर अगले 7 दिनों तक मौजूद रहकर कार्य का मुआयना करेंगे। जहां जहां बोरिंग का कार्य होना है वहां एक महीने में कार्य पूर्ण कराएं। डीसीएनआरएलएम द्वारा रोड निर्माण निरीक्षण के तहत अवगत कराया गया कि कई स्थानों पर बोरिंग करने के बाद गड्ढा बनाकर छोड़ दिया गया है, गांव में पाइपलाइन बिछा दी गई है किंतु टंकी का निर्माण नहीं हुआ है, 10 गांव में कार्यदाई संस्था द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है, जिसपर जिलाधिकारी ने एक्सईएन जल निगम के प्रति नाराजगी व्यक्त की।

जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 8 गांव का निरीक्षण किया गया जहां सिर्फ सिकरारा में कार्य होते हुए पाया गया बाकी स्थलों पर बेहद कम प्रगति पाई गई और कई जगहो पर गड्ढे खोदे हुए पाये गये जिन पर मिट्टी नहीं डाली गई है। इस पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को लंबित कार्य को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम, अपर जिलाधिकारी द्वय राम अक्षयबर चौहान, गणेश प्रसाद सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

25 हजार का इनामिया गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। खुटहन थान अंतर्गत पुलिस व एसटीएफ वाराणसी की संयुक्त टीम ने 25 हजार रुपये के ईनामिया व गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त संदीप कुमार प्रजापति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक, डा0 अजय पाल शर्मा के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी शाहगंज के पर्वेक्षण मे स्थानीय पुलिस बल व एसटीफ टीम वाराणसी द्वारा थाना खुटहन जौनपुर से संबंधित अभियुक्त संदीप कुमार प्रजापति पुत्र भुलई राम प्रजापति ग्राम खानपुर अकबर थाना सरायख्वाजा जौनपुर जो वांछित चल रहा थाम, जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा 25000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था जिसे तिघरा चौराहे से सोमवार रात गिरफ्तार कर मंगलवार को अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए संबंधित न्यायालय भेजा गया।

जिलाधिकारी ने अब्दुल्लागंज पावरहाउस का किया निरीक्षण

निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु अधिकारियों को किया निर्देशित

उमाकान्त लाला, ब्यूरो चीफ

शाहजहाँपुर। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने अब्दुल्लागंज स्थित विद्युत पॉवरहाउस का निरीक्षण कर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अब्दुल्लागंज पावरहाउस के निरीक्षण के दौरान कण्ट्रोल रूम , यार्ड , सहित उपस्थित पंजिका , शिकायत पंजिका , विद्युत आपूर्ति से संबंधित लॉग बुक समेत अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर जानकारी ली। कई पंजिकाओं के पृष्ठ प्रमाणित न मिलने पर अधिशासी अभियंता को फटकार लगाते हुए पृष्ठ प्रमाणित करने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि नियमानुसार विद्युत आपूर्ति हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। किसी भी दशा में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कन्ट्रोल रूम में एक – एक कर सभी क्षेत्रों के फीडर पर लोड के विषय में जानकारी ली। अधिशासी अभियन्ता ने जानकारी देते हुये अवगत कराया कि ओवर लोडिंग की समस्या कम हुई है। लाइनलॉस पर निरन्तर कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि लाइनलॉस कम किया जाये। तथा परिसर एवं यार्ड में सफाई कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही उन्होने विद्युत् यार्ड की बॉउण्ड्रीवाल करवाने के भी निर्देश अधिशासी अभियंता को देते हुये कहा कि सुरक्षा मानको का विशेष ध्यान रखा जाये तथा सुरक्षा उपकरणें का उपयोग आवश्यक रूप से हो यह भी निश्चित किया जाये। पावर हाउस में आने वाली सभी शिकायतों का निस्तारण कराने का निर्देश दिया।

अम्बरीष सक्सेना ग्रा प ए लखनऊ मण्डल के प्रवक्ता एवं आर एल पाडेय लखनऊ के जिला महामंत्री मनोनीत

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। ग्रामीण पत्रकार एसोसियेशन उत्तर प्रदेश के मण्डल अध्यक्ष अतुल कपूर ने वरिष्ठ पत्रकार अम्बरीष कुमार सक्सेना को लखनऊ मण्डल का प्रवक्ता घोषित किया। तथा लखनऊ जिला कार्यकारिणी का गठन गोयल पैलेस (निकट लेखराज मेट्रो स्टेशन) में किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्रा प ए के प्रदेश महासचिव कृष्ण गोपाल गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अतुल कपूर एवं मंडल महामंत्री संजय सिंह की निगरानी में सर्वसम्मति से जिला कार्यकरिणी का गठन किया गया। जिसमें जिलाध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव षाजनष,जिला महामंत्री आर एल पांडेय,सौरभ सैनी,जिला मंत्री अब्दुल फुरकान,इरफान उर्फ सद्दाम शेख,संगठन मंत्री अमित श्रीवास्तव,विधि परामर्शदात्री अनीता सिंह,मोहनलाल गंज तहसील अध्यक्ष दिलीप कुमार, मलिहाबाद तहसील अध्यक्ष मनोज शर्मा को मनोनीत किया गया।

पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य पंकज कुमार श्रीवास्तव ने डीआरएम से की चर्चा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

वाराणसी। मण्डल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के वाराणसी कार्यालय में पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य पंकज कुमार श्रीवासव ने मिलकर रेल यात्रियों एवं कर्मचारियों के हित में कई सुझाव दिये। जेड. आर. यू. सी, सी, सदस्य पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मण्डल रेल प्रबंधक वी. के. श्रीवास्तव

को बनारस से चलने वाली बहराइच वाया अयोध्या, गोण्डा तक एवं बहराइच से बनारस तक चलने वाली इण्टर सिटी एक्सप्रेस का संचालन रेल यात्री हित में अविलम्ब प्रारम्भ किये जाने हेतु पत्र दिया। वाराणसी मण्डल के नवनियुक्त उर्जावान प्रबंधक को शुभकामनाएँ देते हुये भाजपा नेता पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वाराणसी मंडल के लगभग रेलवे परिक्षेत्रों का चौमुखी विकास होगा । वार्ता के समय वाराणसी मंडल के कई वरिष्ठ रेल अधिकारी मौजूद थे।

सरस्वती डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने किया नि:शुल्क दंत परीक्षण

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। सरस्वती डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, तिवारीगंज, लखनऊ के पब्लिक हेल्थ डेन्टस्ट्री विभाग की ओर से ष्ओरल हाइजीन दिवस (व्तंस भ्लहपमदम क्ंल) के उपलक्ष्य में नगर के स्टेशन रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (CMS) में दो दिन का निःशुल्क दन्त चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर का मुख्य उदेश्य बच्चों को दांत से सम्बन्धित बीमारियों के बारे में अवगत कराना था । इस दन्त शिविर में लगभग 800 बच्चों और विद्यालय के समस्त अध्यापकों का निःशुल्क दन्त चेकअप किया गया और उनको मुख स्वस्थ रखने के फायदे और सही तरीके से ब्रश करने की विधि के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। इसके साथ साथ सभी लोगों को निःशुल्क एजुकेशनल पैम्फलेटस और ओरल हाइजीन किट भी बाटी गयी।

इस दन्त परीक्षण को सफल बनाने में सरस्वती डेंटल कॉलेज के प्रेसीडेंट डा० रजत माथुर, प्रधानाचार्य डा० के० एन० दुबे, विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एवं डेटिस्ट्री डा० पल्लवी सिंह, एवं सीनियर लेक्चरर डा० खुशबू अरिफ एवं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की प्रिंसिपल दीपाली गौतम, हेड मिस्ट्रस सविता मखीजा इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

यूपी सरकार की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में की शिकायत

संवाददाता

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहर्रम के दिन घोषित छुट्टी होने के बाद भी छात्रों की छुट्टी निरस्त कर स्कूल बुलाए जाने के मामले की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को शिकायत भेजी है। अपनी शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने कहा राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। लेकिन मुहर्रम के दिन स्कूलों की छुट्टी निरस्त की गई है।जो भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता के मौलिक सिद्धांत के उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए राज्य में संवैधानिक मर्यादाओं को पूर्ण रूप से स्थापित कराने को कहा है।

क्षेत्र के चहुंमुखी विकाश के लिय गृह मंत्री अमित शाह से मिले विधायक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण की मांग और क्षेत्र में कराए गये चतुर्दिक विकास को लेकर विधायक रमेश चन्द्र मिश्र ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंगलवार को उनके कार्यालय में मुलाकात किया। बदलापुर विधानसभा को आदर्श विधानसभा के रूप में तब्दील करने की दिशा में उन्होंने समस्याओं की जानकारी देते हुए उसका निस्तारण करने की मांग किया। उन्होंने बदलापुर विधानसभा में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए लंबित पड़े विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने की दिशा में, उनसे आग्रह किया। गृहमंत्री शाह ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए भरोसा दिलाया कि बदलापुर विधानसभा के विकास की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। विधायक मिश्र ने गृह मंत्री शाह को राजनीति का चाणक्य, कुशल संगठन कर्ता व राजनीतिज्ञ तथा देश हित व जनहित में कठोर निर्णय लेने के लिए पहचाने जाने वाले व सरल व्यक्तित्व बताया। विधायक ने उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।

देवांश अस्पताल से बच्चा चोरी होने का मामले का खुलासा

दंपत्ति और देवांश अस्पताल ने मिलकर बच्चे को बेच दिया था कोतवाली नगर पुलिस ने बच्चे को किया बरामद

(डॉ अजय तिवारी जिला संबाददाता)

'अयोध्या। थाना महाराजगंज के पौसरा निवासी दंपति ने बच्चे को था खरीदा, दोनों दंपत्ति के बच्चे देवांश अस्पताल में हुए थे पैदा, एक दंपत्ति हुई बेटी तो दूसरे को हुआ था बेटा, बेटी होने वाले दंपत्ति ने बेटे को खरीद कर घोषित किया जुड़वा बच्चे, अस्पताल ने ले लिया पैसा,बेटा पैदा करने वाले दंपत्ति को पैसा ना मिलने पर कोतवाली नगर में की शिकायत, पुलिस ने जांच करते हुए बच्चे को किया बरामद, 2 महीने के बच्चे को लखनऊ चाइल्ड केयर सेंटर में कराया गया भर्ती, पैदा करने वाले दंपति ने बच्चे को पालन पोषण से किया था इनकार।

मणिपुर में अमन के लिये रालोद ने निकाला कैंडिल मार्च

संवाददाता

लखनऊ। मणिपुर हिंसा में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि देने तथा मणिपुर में शान्ति व अमन चौन कायम करने हेतु राष्ट्रीय लोकदल ने राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 30 जुलाई को युवा तथा छात्र रालोद द्वारा कैंडल मार्च निकाला जिसमें रालोद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह ने कहा कि मणिपुर में जातीय संघर्ष ने सामाजिक ताने बाने का तहस नहस कर दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद जयन्त चौधरी तथा रालोद कार्यकर्ता मणिपुर शान्ति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मणिपुर जैसे खूबसूरत राज्य को तबाह किया जा रहा है और बढ़ते जातीय संघर्ष में लोगों को जानबूझकर एक दूसरे के खिलाफ खडा किया जा रहा है। मणिपुर के लोगों के मन में डर और अनिश्चितता है मणिपुर में स्थिति बहुत गम्भीर है। मणिपुर में हजारों लोग बेघर हो गये हैं। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा अभी कुछ दिनों पहले महिलाओं, आदिवासियों, दलितों तथा गरीबों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया जा चुका है।

उप मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम उमड़े फरियादी

जन समस्याओं का त्वरित गति से किया जाए निदान : केशव प्रसाद मौर्य

संवाददाता

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने– 7 कालीदास मार्ग स्थित आवास कैम्प कार्यालय पर विभिन्न जनपदों से आये लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक–एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का निराकरण इस प्रकार किया जाय कि समस्याग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट रहें और उन्हें दुबारा कहीं भटकना न पड़े और बार–बार चक्कर न लगाने पड़ें। अफसर ध्यान रखे कि समस्या जिला स्तर पर हल हो जाये। किसी व्यक्ति बार बार भटकने को मजबूर न हो। उसे लखनऊ की दौड़ लगानी न पड़े। उन्होंने महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों की समस्याओं व शिकायतों को सुना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से निदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।जनता दर्शन में भूमि विवाद ,दुर्घटनाओं से संबंधित ,अवैध कब्जे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आवंटन, स्कूल निर्माण, भूमि पट्टा, कब्जा दिलाने, अतिक्रमण हटाने,सड़क बनवाने, विजली, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराने, आदि से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने रखी। उप मुख्यमंत्री फरियादियों के पास खुद चलकर गये और एक एक व्यक्ति की समस्या को उनसे सीधे रूबरू होकर सुना। जनता दर्शन मे फिरोजाबाद ,हरदोई, आजमगढ़ प्रयागराज ,कानपुर देहात ,अलीगढ़ ,बस्ती, संभल, जालौन, बुलंदशहर ,बहराइच, जौनपुर, ललितपुर, अंबेडकर नगर ,हापुड़, मेरठ, हमीरपुर, इटावा, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, मऊ, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर ,उन्नाव, सोनभद्र, झांसी, प्रतापगढ़ ,जालौन, गाजीपुर ,बलिया, सीतापुर, फतेहपुर ,अमरोहा, रायबरेली, सहित 3 दर्जन से जिलों से कई सैकड़ा लोगों ने आकर अपनी समस्याएं रखी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्याओं के निस्तारण के बावत गोण्डा, ललितपुर, झांसी,के जिलाधिकारियों, रायबरेली, गाजीपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षको व अन्य जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों व शासन के उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता भी की।

पर्यटन क्षेत्र में असीमित सम्भावनाओ के कारण आगे आ रहे निवेशक

संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्द्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा सदस्यों द्वारा चयनित पर्यटन स्थलों का विकास कराया जा रहा है। इस योजना में प्रत्येक विधानसभा के विकास हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी एवं अतिरिक्त आवश्यकता होने पर धनराशि का वहन विधायक निधि सीएसआर फण्ड से किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2022–23 में चार विधानसभा क्षेत्रों हेतु 162.47 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन सेक्टर एक उभरता हुआ क्षेत्र है। जिसमें रोजगार के साथ पूंजी निवेश तथा राजस्व अर्जन की भरपूर संभावनायें हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों में चिन्हित धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथा चर्चित पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि विधानसभा सदस्यों द्वारा चिन्हित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए परियोजनायें चिन्हित की गयी हैं। जयवीर सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में 367 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 180.33 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 76.20 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी। इस धनराशि से संबंधित जनपदों में पर्यटन योजनाओं का विकास किया जा रहा है। विख्यात एवं अल्पज्ञात स्थलों तक पहुंच के लिएअवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए संकेतक भी लगवाये जा रहे हैं। पर्यटन सेक्टर में असीमित संभावनाओं को देखते हुए निवेशक आगे आ रहे हैं। निवेशकों के प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग तेजी से कार्य कर रहा है।

बहुत सी परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

प्रदेश में जातिवादी राजनीति फिर ले रही अंगड़ाई

समाजवादी नेता की बयानबाजी नफरत से भरी: मृत्युंजय दीक्षित

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)

उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। जैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों ने आई.एन.डी.आई.ए. नाम से अपना नया महागठबंधन बनाया वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमो ने अपनी अपनी धड़ेबंदी और बयानबाजी आरम्भ कर दी।

चुनावी प्रक्रिया के पहले सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनैतिक दल स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी भूमिका का भी निर्धारण करते हैं। इसी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोनों खेमों की बढ़त को रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बहिन मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाजवदी पार्टी ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है और बहिन मायावती की ओर से बहुत सधे हुए बयान आ रहे है। इसके उलट विगत विधानसभा चुनावें मे जो दल समाजवादी पार्टी के खेमे में थे उनमे से अधिकांश भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं जबकि कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों से भाजपा नेतृत्व लगातार संपर्क स्थापित कर उनसे बातचीत कर रहा है ।

प्रदेश में लगभग सभी दल जातिगत आधार पर अपना गणित फिट करने के लिए काम कर रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आई. एन.डी.आई.ए. गठबंधन जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है, इस विषय पर समाजवादी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और सपा का बौद्धिक प्रकोष्ठ संगोष्ठियां आयोजित कर वातवारण को गरमाने की सियासत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए लगातार काम कर रही है और वह भी दूसरे दलों के ऐसे नेताओ को जिनका अपना एक बड़ा जातिगत आधार है उन्हें पार्टी में शामिल करने का अभियान चला रही है।

विगत दिनों प्रदेश की राजनीति में दो ऐसे बयान आये हैं जिनसे यह साफ हो गया है कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश में जातिगत राजनीति पुनर्जीवित की जा रही है।

समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते थे और मंत्री बने थे ये 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर अपने कुछ सहयोगियों के साथ सपा में वापस जाकर सपा के टिकट पर लड़े थे और हार गये थे, लोकसभा चुनावों को देखते हुए अपनी राजनैतिक टीआरपी बढ़ाने के लिए बेहद व्याकुल हैं । वह लगातार ओछे और विकृत बयान दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वह ऐसा करके समाजवादी पार्टी के हित में काम कर रहे हैं ।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने सर्वप्रथम हिंदू जनमानास के सबसे पवित्र धर्मग्रंथ रामचरित मानस पर ही अभद्र टिप्पणी की फिर संत समाज का भी अपमान किया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निजी हित के लिए मौर्या हिंदू समाज के खिलाफ नफरत उड़ेल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानो से हिंदू समाज लगातार आहत हो रहा है। जब रामचरित मानस का प्रकरण थोड़ा ठंडा पड़ने लगा तो उन्होंने हिंदू समाज के सर्वाधिक पवित्र तीर्थों से एक बदरीनाथ धाम को लेकर ही एक विवादित बयान दे डाला। सपा नेता के इस बयान से राजनीति गर्मा गयी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस विवाद में कूद पड़े और मौर्या को चेतावनी दे डाली। वहीं बसपा नेत्री मायावती ने भी बदरीनाथ धाम के मुददे पर सपा नेता मौर्य पर तीखा हमला बोला है।

स्वामी प्रसाद मौर्य घोर जातिवादी व नफरत से भरे नेता हैं जो अपने बयानों को और कड़वा बनाकर वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को चेतावनी जारी कर कह रहे हैं कि भाजपा के लोग साजिश के तहत मंदिर– मस्जिद के मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोजने की बात करेंगे तो यह परंपरा उन्हें महंगी पड़ेगी अगर हर मंदिर में मस्जिद खोजोगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजना शुरू करेंगे क्योकि इतिहास और साक्ष्य के प्रमाण हैं कि जितने भी हिंदू धर्म के तीर्थस्थल हैं वह सभी बौद्ध मठ पर बने हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस जहर उगलने का कारण यह आभास है कि 2024 तो दूर की बात है अब 2027 में भी उनके राजनैतिक भविष्य का सूर्योदय नहीं होगा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का कहना है कि सनातन धर्म का अपमान करना सपा और उनके नेताओं की घृणित मानसिकता बन चुकी है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा केदारनाथ, बदरीनाथ और श्री जगन्नाथपुरी के विषय में दिया गया बयान न सिर्फ विवादित है अपितु उनकी ओछी मानसिकता व तुच्छ राजनीति का परिचायक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में ज्ञानवापी सर्वे के विरोध में मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करते हुए सभी हिंदू मंदिरों के सर्वे की मांग करते हुए दावा किया था कि बदरीनाथ धाम बौद्ध मठ के ऊपर बना है।

फूलन देवी पर राजनीति का नया दौर – कुख्यात डकैत फूलन देवी जो जो उप्र के एक छोसे गांव गोरहा के पूर्वा में एक मल्लाह के घर में जन्मी थीं, परिवार के ही कुछ लोगों और फिर गांव के दबंगों ने उन पर अमानवीय अत्याचार किये थे। कालांतर में फूलन ने उनसे अपना बदला लिया और डकैती डालने लगीं। 1994 में सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से वापस ले लिया और उनको राजनीति में ले आए। फूलन 11वीं और 13वीं लोकसभा में सांसद बनीं और 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या हो गई। फूलन की मौत के 22 वर्ष बीतने के बाद जातिगत राजनीति करने के लिए उसको जिंदा करने के प्रयास हो रहे हैं।

प्रदेश सरकार में शामिल निषाद पार्टी ने फूलन देवी की मौत के 22 वर्ष बीत जाने के बाद उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। निषाद पार्टी के नेता डा . संजय निषाद का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों को पत्र लिखकर मांग की है कि वीरांगना फूलन देवी मछुआ समाज की ही नहीं अपितु विश्व की महिलाओं के लिए आदर्श रही हैं। उन्होंने समाज को जागरुक करने के लिए अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला। फूलन देवी ने जुल्म, अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं के सम्मान की रक्षा और उनके हक के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी है। निषाद पार्टी वीरांगना फूलन देवी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है।

यह बात सही है कि फूलन देवी ने अपने जीवनकाल में बहुत अत्याचार सहे हैं किंतु क्या जातिगत आधार पर उन्हें वीरांगना कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फूलन देवी की मौत के 22 साल बाद सीबीआई जांच की मांग करना कहां तक उचित है ? यह तथाकथति महज राजनैतिक स्वार्थ और स्टंट की राजनीति नहीं तो और क्या है? क्या फूलन देवी जैसी महिला को वीरांगना कहना उचित है। जातिवाद की राजनीति के कारण आजकल स्टंटबाजी भी खूब हो रही है । फूलन देवी की आड़ में राजनीति चमकाने के लिए समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने भी फूलन देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और बयान जारी किया।

इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के समक्ष भी राजनैतिक चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है। पहली बात यह है कि निषाद पार्टी भाजपा के गठबंधन में शामिल है और भाजपा सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए संकल्पित है। अगर भाजपा कुछ कहती है तो उसे नुकसान हो सकता है या सहयोगी बिदक भी सकता है इसलिए भाजपा ऐसे मुददों से फिलहाल दूरी बनाकर ही चलती है।

आने वाला चुनाव काल उत्तर प्रदेश में एक नए जातिवादी उबाल का साक्षी हो सकता है अतः राष्ट्रवादियों को एकजुट रखना भाजपा की प्राथमिकता होगी।

चौकीदारों की समस्याओं को लेकर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से की मुलाकात

मृत्युंजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट

राजधानी लखनऊ रूआज दिनांक एक अगस्त 023 को उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरी (चौकीदार)के समस्या, राज्य कर्मचारी का दर्जा एवं न्यूनतम वेतन मान 20500/–से 18500/–करने हेतू उत्तर प्रदेश उप मुख्य मंत्री माननीय बृजेश पाठक जी,एवं वन मंत्री माननीय अरूण कुमार जी से शिष्टाचार मुलाकात लोक जन समाज पार्टी(भारत)के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी,उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार त्रिपाठी,हरदोई जनपद के चौकीदार दिलदार खाँ,मऊ जनपद से शिवनाथ राजभर,लखनऊ से राजेन्द्र पाण्डेय मौजूद रहे।और माननीय मंत्रीगण से वार्ता सफल रहा और जल्द ही चौकीदार वर्ग के हित में कार्य करते हुए उनके मांग को जायज ठहराते हुए माँग पूरा करने का आश्वासन दिए।

प्रेमचंद की जयंती पर आनलाइन कार्यक्रम आयोजित

संवाददाता

लखनऊ। नवयुग कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती पर एक कार्यक्रम आनलाइन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था, वर्तमान समय में प्रेमचन्द की प्रासंगिकता इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रो नलिन रंजन सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, केकेसी कालेज एवं विशिष्ट अतिथि प्रो श्रुति प्रोफेसर हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए हिंदी विभाग की डा अमिता रानी सिंह ने कहा कि प्रेमचंद ने दलित, शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज उठाई। प्रो नलिन रंजन सिंह का परिचय अंकिता पांडे ने दिया। प्रो नलिन रंजन सिंह ने कहा कि अगर हम वर्तमान समय में प्रेमचन्द की प्रासंगिकता की बात करें तो आज हम 76वर्ष बाद भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जो प्रेमचंद ने अपने उपन्यास और कहानियों में लिखीं इसीलिए प्रेमचंद की सारी रचनाओं के पात्र आज भी प्रासंगिक हैं। सेवासदन, प्रेमाश्रय, के लगभग 100वर्ष बीत जाने पर भी उन उपन्यासों के चरित्र हमारे आसपास ही दिखते हैं। रंगभूमि का नायक अंधा भिखारी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर कहता है कि अगर सौ बार झोपड़ी जलाएंगे तो हम सौ बार बनाएंगे। निर्मला उपन्यास बेमेल विवाह की समस्या आज भी है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद को झूठ और दिखावे से नफरत थी वे जैसा देखते थे वही लिखते थे।वे चाहते थे मजदूरों और किसानों के हक में निर्णय लिए जायं। कफन कहानी एक मेटाफर है भूख और बेबसी की कहानी, अतीत, वर्तमान और भविष्य की कहानी। मेघना यादव ने प्रो श्रुति का परिचय दिया। प्रो श्रुति ने कहा प्रेमचन्द कालजयी रचनाकार थे। उन्होंने उनकी दो कहानियां दोनो तरफ से एवं जिहाद पर प्रकाश डाला। जो कि गांधी वादी और धर्मान्तरण पर आधारित है। प्रेमचंद की कथनी और करनी एक थी। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो मंजुला उपाध्याय ने कहा कि प्रेमचंद जो अनुभव करते थे, वही लिखते भी थे। वे जिस समय में जी रहे थे वही स्थिति उनकी रचनाओं में दिखता है। हमारे समाज में बदलाव हुआ है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज प्रेमचंद की जयंती पर सबको बधाई देती हूं। अंत में धन्यवाद ज्ञापन देते हुए हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रो मंजुला यादव ने कहा कि मैं सभी का धन्यवाद देती हूं, अपने दोनों वक्ताओं का, प्राचार्या जी का एवं हिंदी विभाग और महाविद्यालय के सभी सहयोगियों का। आज की इस संगोष्ठी संपन्न से हमारी छात्राएं अवश्य लाभान्वित होंगी। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्रवक्ताएं डा सृष्टि श्रीवास्तव डा अपूर्वा अवस्थी, डा सुनीता सिंह, डा चंदन मौर्या,आभा दुबे, एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।

पीसीपीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई

संवाददाता

लखनऊ। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को प्रसवपूर्व निदान तकनीकी,विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण अधिनियम(पीसीपीएनडीटी), 1994 की जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डा. के. डी. मिश्रा ने कहा कि पीसीपीएनडीटी के मद में जो भी रकम है उसका उपयोग अधिनियम से संबंधित विकास कार्यों पर किया जाए। जिसके जो भी पेपर वर्क होना है वह शीघ्र पूरा करें। पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डा.के.डी.मिश्रा ने बताया कि जनपद में लगभग 500 पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेन्टर हैं। उन्होंने समिति को डायग्नोस्टिक सेन्टर के पंजीकरण की प्रक्रिया की भी जानकारी दी। इस मौके पर अवंतिबाई जिला महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. संघमित्रा, बलरामपुर अस्पताल से बाल रोग विशेषज्ञ डा. हिमांशु चतुर्वेदी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रेडियोडायगनोसिस विभाग से ज्योति, सहायक निदेशक, सूचना दिनेश गर्ग, जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार त्रिपाठी, पीसीपीएनडीटी के जिला समन्वयक शादाब, विधिक सलाहकार प्रदीप कुमार मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संजीव कुमार श्रीवास्तव, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफॉर) से ज्योति मिश्रा और राष्ट्र सेविका समिति से मधुबाला मौजूद रहीं।भ्रूण हत्या रोकने के लिये सरकार यह लागू किया है। इस अधिनियम के तहत गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना या करवाना कानूनन दंडनीय अपराध है। साथ ही अल्ट्रासाउंड केंद्र द्वारा फॉर्म–एफ भरकर अपलोड किया जाता है।

जनता दरबार में राजीव करते है लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान

संवाददाता

लखनऊ। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी राजीव मिश्रा लोगों में अपने सेवाभाव के कारण खासे लोकप्रिय है। राजीव मिश्रा के अथक प्रयासों से कोरोना काल में जो योगदान ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का रहा है व कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। राजीव भैया के नाम से लोगों में लोकप्रिय राजीव मिश्रा भाजपा के अवध प्रांत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। जिनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में काफी धूम भी मचा रही है। वही पार्टी संगठन के कार्यों में राजीव मिश्रा का कोई दूसरा सानी नहीं है।

आईपीएस प्रभाकर चौधरीः 13 साल में 21 बार तबादला

संवाददाता

लखनऊ। बरेली के जोगी नवादा में माहौल बिगड़ने से रोकने की कोशिश के दौरान तेजतर्रार आईपीएस अफसर एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला चर्चा में है। स्थिति को काबू करने के लिए रविवार को एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। कुछ अराजकतत्व गिरफ्तार भी हुए। जोगी नवादा क्षेत्र छावनी में तब्दील है। मौके पर बरेली पुलिस और पीएसी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। प्रभाकर चौधरी माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को चिह्नित कर जब तक कार्रवाई करते तब तक उनके तबादले का आदेश जारी हो गया।उनके कड़े तेवर के बीच अराजक तत्वों के मंसूबे सफल नहीं पा रहे थे।2010 बैच के आईपीएस प्रभाकर चौधरी का 13 साल की सेवा में 21 बार तबादला किया जा चुका है। कई जिलों में एसएसपी और एसपी रह चुके हैं। सादगी और ईमानदार छवि के अलावा तबादलों के लिए भी चर्चित हैं। बरेली की उन्होंने चार महीने पहले कमान संभाली थी। बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा की शाह नूरी मस्जिद के पास बीते दिनों डीजे की धुन पर कुछ अराजक तत्वों ने कांवड़ियों के जत्थे में शामिल होकर रंग उड़ाया था। इसके बाद पथराव हुआ। प्रभाकर चौधरी ने तत्परता दिखाते हुए मामला संभाल लिया था। मामले में पार्षद के पुत्र अमित की ओर से पूर्व पार्षद उसमान अल्वी समेत 100 से 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो जोगी नवादा चौकी इंचार्ज अमित कुमार ने 200 से 250 अज्ञात लोगों पर एफआईआर कराई। पुलिस मामले को लेकर जांच जारी है।इस बीच रविवार को फिर कुछ लोगों ने नए रूट से जाने की जिद की। जबकि दूसरे समुदाय के लोग नई परंपरा बताकर जत्था और उसके साथ डीजे ले जाने का विरोध कर रहे थे। डीएम और एसएसपी समेत कई अफसर मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों से वार्ता की। इस बीच कांवर जत्थे में शामिल कुछ शरारती तत्वों ने डीएम और एसएसपी के सामने ही अवैध तमंचों से फायरिंग कर दी। माहौल बिगड़ने लगा जिसके चलते पुलिस को मामूली बल प्रयोग करना पड़ा लेकिन इसके चार घंटे बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी को बरेली से हटाकर पीएसी की 32वीं बटालियन में सेनानायक बना दिया गया। एसपी सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान को बरेली का एसएसपी बनाकर भेजा गया है।

प्रभाकर चौधरी को 12 मार्च को बरेली भेजा गया था। पूर्व डीजीपी डीएस चौहान ने काफी समझकर उन्हें बरेली भेजा था। उस वक्त बरेली में माफिया अतीक अहमद और अशरफ का प्रकरण चल रहा था। उन्होंने इसमें कई लोगों को जेल भेजा, मामला शांत हो गया। करीब एक महीने से प्रभाकर चौधरी बरेली से हटने की कोशिश में लगे थे। लखनऊ के उच्च अफसरों से उन्होंने कई बार खुद को बरेली से हटाने को कहा लेकिन नहीं हुआ।

मणिपुर घटना आजाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक पीड़ादायक :प्रमोद तिवारी

संवाददाता

लखनऊ। प्रमोद तिवारी, सांसद, उप नेता राज्य सभा, एवं सदस्य, केन्द्रीय कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी ने कहा है कि मणिपुर भ्रमण पर विपक्षी गठबंधन (इण्डिया) के सांसदो ने वहां के हालात को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के सांसदों ने वहां पीडितो से मुलाकात की, और पीड़ितों ने जिस तरह की घटना का बयान किया है वह आजाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक पीड़ादायक है। श्री तिवारी ने कहा कि जिस बर्बरता और वीभत्सता के साथ मणिपुर में एक मां के सामने बेटी तथा परिवार के लोगों की नृशंस हत्या की गयी और जिस तरह से वहां के हालात पर केन्द्र एवं मणिपुर प्रदेश की भाजपा सरकारे मूकदर्शक बनी रहीं है वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के सांसदों ने मणिपुर के महामहिम श्री राज्यपाल जी से भी मुलाकात की और पीड़ितो से हुई मुलाकात का दर्द उन्हें सुनाया है। श्री तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी मणिपुर की भयावहता की जानकारी हैं इसलिए वह संसद में बयान देने से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के सीमावर्ती राज्य में अशांति के भयावह दौर में अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और हरहाल में संसद के जरिए देश की जनता को असलियत बताना चाहिए। उन्होने कहा कि मणिपुर जल रहा है, श्रीनगर में छुटटी पर आये फौजी का अपहरण हो रहा है और विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा समेत मंहगाई और बेरोजगारी पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला चुका है। श्री तिवारी ने कहा कि देश मे उत्पन्न इन चिन्ताजनक हालातों के बीच भाजपा सरकार संसद मेंअविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के बावजूद भी 10 दिन की अवधि का सरकारी कामकाज निपटाने में नैतिकता तथा संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन करके राजकाज को भी संदिग्ध दिशा दे रही है। उन्होने कहा कि संसद की गरिमा और परम्परा तथा संविधान, सरकार को सदैव यह निर्देशित करता रहा है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बीच शोर शराबे का सहारा लेकर गैरकानूनी तरीके से सरकारी कामकाज निपटाना औचित्य का सवाल खड़ा करता है।श्री तिवारी ने कहा है कि सरकार की गलत आर्थिक दिशा तथा बाजार में अनियंत्रण के चलते इस समय सब्जियों तक की कीमतों में जून की अपेक्षा जुलाई में मंहगाई का ग्राफ दोगुना हो गया है। देश के कुछ हिस्सों मे भीषण बाढ़ तथा कुछ हिस्सों मे सूखे के हालात के कारण किसान दोनों स्थितियों में फसल की लागत तक वापस पाने की स्थिति मे नही है, इसके बावजूद मोदी सरकार खेती किसानी के लिए एक भी कारगर कदम नहीं उठा रही है।

पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन

संवाददाता

लखनऊ। इप्सेफ के आह्वान पर देश भर के राज्यों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पदाधिकारियों को बुलाकर बात की। वीपी मिश्र के नेतृत्व में इप्सेफ के आवाह्न पर सभी राज्यों के हजारों कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली का भी विशेष योगदान रहा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में क्रमशः पुरानी पेंशन की बहाली, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन, आउटसोर्सिंग संविदा वर्कचार्ज कर्मचारियों केविनियमितीकरण एवं न्यूनतम वेतन व नियमावली बनाना हैं। रैली,प्रदर्शन के पूर्व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वीपी मिश्र के दूरभाष पर इप्सेफ के प्रतिनिधि मंडल को प्रातः 9रू30 बजे वार्ता के लिए आवास पर आमंत्रित किया और कहा कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं है।पुरानी पेंशन बहाली पर कमेटी की संस्तुतिया प्राप्त होते ही भारत सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय बहुत जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा नियमावली व्यवस्था एवं राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करने की मांग पर भी भारत सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय करने पर प्रभावी कदम उठाएगी। श्री सिंह ने आश्वासन दिया कि कर्मचारी सरकार के महत्वपूर्ण अंग इसलिए उनकी पीड़ा को दूर किया जाएगा। श्री मिश्रा ने बताया कि रैली में उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश ,राजस्थान ,छत्तीसगढ़,दिल्ली ,पंजाब ,हरियाणा ,आंध्र प्रदेश ,तेलंगाना ,हिमांचल कर्नाटक ,जम्मू–कश्मीर आदि राज्यों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की टोपी लगाकर आक्रोश व्यक्त किया और चेतावनी दी सितंबर अक्टूबर में रामलीला मैदान में कम से कम दो लाख कर्मचारी रैली प्रदर्शन करके बड़े और आंदोलन आगे बढ़ाने की चेतावनी देंगे। रैली से पूर्व ही इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आमंत्रित करके जल्द सकारात्मक निर्णय करने का आश्वासन देने के लिए इप्सेफ द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद द्वारा सभा में प्रस्तुत ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा यदि पुरानी पेंशन की बहाली एवं अन्य मांगों पर एक माह के अंदर निर्णय नहीं किया गया तो इपसेफ बहुत बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। जिसका सत्ताधारी दल को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। सभा को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक सतीश कुमार पांडेय ,गाजियाबाद से राजकुमार सिंह, नरेंद्र शर्मा आदि ने इप्सेफ को विश्वास दिलाया कि उनके आवाह्न पर प्रदेश के लाखों कर्मचारी शिक्षक सभी आंदोलन कार्यक्रम को पूरा सहयोग करेंगे, वे हर कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे।

आईएएस अफसर डा. नवनीत सहगल हुए रिटायर

संवाददाता/लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बसपा, सपा व बीजेपी सरकार में अहम भूमिका में रहे आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल 35 साल की लंबी प्रशासनिक सेवा पूरी कर आज सोमवार को रिटायर हो गये हैं। वर्तमान में वह यूपी में अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण का कार्यभार संभाल रहे थे। आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल मायावती से लेकर अखिलेश और योगी आदित्यनाथ तक की कोर टीम में रहे हैं।1988 बैच के आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल बसपा सरकार में मुख्यमंत्री मायावती के सचिव रहे। तब पंचम तल पर वे सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में से एक माने जाते थे।यूपी कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और नवनीत सहगल के पास सीए की डिग्री है। मूल रुप से पंजाब के रहने वाले हैं। शिक्षा बी काम, सीएसीएस, सर्ट ऑफ प्रोफिसिएन्सी इन फ्रेंच हैं। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग1991 में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट देहरादून के पद पर थी। उसके बाद वह हरिद्वार डेवलपमेंट अथारिटी के वीसी रहे। जौनपुर, गौंडा, अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ में डीएम रहे हैं। केंद्र सरकार में वो पंचायती राज विभाग में निदेशक भी रहे हैं। 2007 से लेकर 2012 तक मायावती के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान वो सीएम के सचिव के साथ कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसमें शहरी विकास, बिजली विभाग शामिल है लेकिन 2012 में अखिलेश यादव के सीएम बनने के बाद वो दो सालों तक धार्मिक मामलों के प्रमुख सचिव बनाए गए। 2014 में अखिलेश की कोर टीम में शामिल हुए और सूचना विभाग के प्रमुख बने। यूपीडा के भी प्रमुख रहे जिसमें आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे का काम रिकार्ड टाइम में पूरा किया। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद वो हाशिए पर चले गए और खादी विभाग की जिम्मेदारी संभाली।

हिन्दी सांध्य दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित ।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI संन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1

deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।